www.tamsasanket.com
वर्षः 05 || अंक 337 || लखनऊ
शनिवार
14 मार्च 2026 || पृष्ठः 04 || मूल्यः ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com
दैनिक
तमसा संकेत
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
» डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदयः 06:15
सूर्यास्तः 06:16
अधिकतमः 36°00
न्यूनतमः 21°00

पेज 03

विशेष समाचार
- ममता आर पार की लड़ाई के मूड में!... >> पेज 02
- ग्रीन कॉरिडोर फेज-2 का लोकार्पण... >>पेज 04
- बेटी के साथ दुबई में फंसीं लारा...

अमेरिका के आगे नरेंदर ने सरेंडर कर दिया, वह अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं

मोदी साइकोलॉजिकली खत्म : राहुल

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा, नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो गए हैं। मोदी अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे, वह अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं और नरेंदर ने सरेंडर कर दिया है। जब मैं यह बात संसद में बोलने जा रहा था तो नरेंद्र मोदी जी भाग कर निकल गए। राहुल गांधी सोमवार को लखनऊ में कांशीराम जयंती पर आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर दिया है। क्योंकि अब अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल कहां से लेंगे? एनर्जी सेक्टर के हालात अभी और खराब होंगे। राहुल ने आगे कहा कि कांशीरामजी समाज में बराबरी की बात करते थे। अगर जवाहर लाल नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। लेकिन आज भाजपा ने समाज को 15 और 85 बांट दिया गया है। फायदा सिर्फ 15% वालों को मिल रहा है। 50% को अलग-अलग कर दिया गया। राहुल जब बोलने के लिए उठे तो कार्यकर्ता राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। तब राहुल ने नसीहत देते हुए कहा, राहुल गांधी जिंदाबाद करने से कोई फायदा नहीं है। इससे कुछ होता नहीं है। होता कैसे है? जो मन बना लेता है कि ये जो हो रहा है, उसे मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूं। कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। दलित राजनीति में बसपा का प्रभाव अब भी बरकरार है, खासकर जाटव समुदाय में उसका भावनात्मक जुड़ाव मजबूत है। दूसरी ओर, भाजपा ने भी पिछले 10 बरसों में दलित वर्गों के बीच संगठन मजबूत किया है और सरकारी योजनाओं के जरिये समर्थन बढ़ाया है, इसलिए कांग्रेस के लिए इस वोट बैंक में बड़ी जगह बनाना आसान नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं- ऐसा नहीं है। मायावती भले ही खुद बहुत ज्यादा नहीं निकलती हों।

राहुल ने ये 3 बातें भी कहीं

नरेंद्र मोदी संविधान की विचारधारा नहीं मानतेः संविधान में जितने भी दलित महापुरुष हुए, उनकी आवाज इसमें है। सावरकर, नाथूराम गोडसे की आवाज इस संविधान में नहीं है। नरेंद्र मोदी कुछ भी कह लें, इस संविधान की विचारधारा को नहीं मानते हैं।

सारा माल अमेरिका का आएगाः मोदी ने कहा है कि 9 लाख करोड़ का माल अमेरिका से खरीदेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे बिजनेस क्या करेंगे। कपास, सोया, फल, बादाम, अखरोट अब अमेरिका के किसान यहां बेचेंगे। अमेरिका में बड़े- बड़े खेत हैं। सारा माल उनका आ जाएगा, सब खत्म कर देंगे।

यूपी में कांग्रेस को मर मिटने वाले 100 लोग चाहिएः अब हमारे पास बड़ा मौका है। हिंदुस्तान की राजनीति बदलें। कांग्रेस को सिर्फ यूपी में 100 लोग ऐसे मिल जाएं जो कह दें कि मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे। काम हो जाएगा हमारा।

लखनऊ एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आने के लिए राहुल गांधी सफेद रंग की कार में बैठे।

कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग उठाएगी कांग्रेस

कांग्रेस ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव पास किया है। तय हुआ है कि राहुल गांधी के माध्यम से संसद में यह मांग उठाई जाएगी। यह पहली बार था, जब राहुल गांधी कांशीराम जयंती से 2 दिन पहले कोई बड़ा इवेंट लखनऊ में करने आए थे। कार्यक्रम में करीब 4 हजार लोग शामिल हुए। दलित वोटर्स की सियासत में कांग्रेस का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। सपा-कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को लगता है कि कमजोर बसपा का वो विकल्प बन सकती हैं। दोनों पार्टियां बसपा को भले ही कमजोर कहने से बचती हैं, लेकिन मायावती पर भाजपा के दबाव में काम करने के आरोप लगाकर इसी कमजोरी को उजागर करने की कोशिश करती हैं।

> "राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान का पूरा डेटा अमेरिका को पकड़ा दिया। हमारा डेटा अमेरिका कहीं भी रख सकता है। हम अपने ही डेटा को चेक नहीं कर सकते हैं। मानो सउदी या रूस ने पूरा तेल अमेरिका को दे दिया। ऐसा ही है। मोदी ने कहा कि 9 लाख करोड़ का माल अमेरिका से खरीदेंगे। मैं पूछना चाहता हूं। हमारे बिजनेस क्या करेंगे। कपास, सोया, फल, बादाम, अखरोट अब अमेरिका के किसान यहां बेचेंगे। अमेरिका में बड़े- बड़े खेत हैं। सारा माल उनका आ जाएगा, सब खत्म कर देंगे। अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। क्योंकि मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। आप बताइए, कहां से खरीदें। आप चाहते हैं रूस से न खरीदें। आप चाहते हो ईरान से न खरीदें।"

कांग्रेस को चाहिए यूपी में मुस्लिम-दलित वोट

सीनियर जर्नलिस्ट हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं- राहुल गांधी इस देश में मुस्लिम-दलित की राजनीति करना चाहते हैं। इसकी वजह भी है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास खुद का कोई वोटबैंक बचा नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि उसे मुस्लिमों और दलितों का पूरा समर्थन मिले। ये दोनों वोटबैंक अकेले 40% हो जाते हैं। ये भी सच है कि इस वोटबैंक के बिना कांग्रेस इस देश की सत्ता पर नहीं पहुंच सकती। राहुल गांधी दलित को पीड़ित दिखाकर उनका समर्थन हासिल करना चाहते हैं।

यूपी में कांग्रेस-सपा का गठबंधन

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन था, तब यूपी में NDA की सीटों की संख्या 36 पर सिमट गई थी। महागठबंधन 43 सीटों पर जीतने में कामयाब रहा। महागठबंधन इसी सफलता को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहता है। सपा भी कांशीराम जयंती को PDA दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर चुकी है। 15 मार्च को यूपी के 75 जिलों में पार्टी के जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम होंगे। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी कहते हैं- मौजूदा समय में बसपा सबसे कमजोर हालत में है। लोकसभा में उसका कोई भी सदस्य नहीं। यूपी के विधानसभा में मात्र एक विधायक है। राज्यसभा में भी दिसंबर के बाद उसके जीरो होने का आसार हैं।

एयरपोर्ट पर अजय राय और पार्टी के सभी बड़े लीडर राहुल गांधी को रिसीव करने पहुंचे थे।

राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा धन अडानी को नहीं दिया

राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा धन अडानी को नहीं दिया। वह है भाजपा का, वह अडानी का नहीं। वह पूरा सिस्टम भाजपा का है। पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। वह अडानी कंपनी में है। यह बात अमेरिका ने पकड़ ली है। इसलिए केस किया है। वह केस मोदी जी को मैसेज है। अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपका पूरा सिस्टम खोल देंगे। लोगों को दिखा देंगे। वह हिंदुस्तान के पीएम नहीं रहे हैं। वह अमेरिका का काम कर रहे हैं। जब मैं ये बात कहने जा रहा था, तब मोदी भागकर निकल गए। आंख से आंख नहीं मिला सकते हैं।

भारत हमारा दोस्त, होर्मुज में सुरक्षित रास्ता देंगे : ईरान

2-3 घंटे में ऐसा होते देखेंगे, ओमान में ड्रोन अटैक- 2 भारतीयों की मौत

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव/तेहरान। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली ने कहा है कि ईरान भारत को सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के बीच दोस्ताना संबंध हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे सवाल पूछा गया कि क्या ईरान भारत को होर्मुज स्ट्रेट में रास्ता देगा। इस पर फतहाली ने कहा, "हां, क्योंकि भारत हमारा दोस्त है। आप इसे दो-तीन घंटे में देखेंगे।" उनके मुताबिक भारत और ईरान के बीच लंबे समय से सहयोग और विश्वास का रिश्ता रहा है। इसी बीच ओमान के सोहर प्रांत में ड्रोन गिरने से दो भारतीय कामगारों की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने एक ड्रोन को मार गिराया था, जिसके बाद उसका मलबा गिरने से यह

हादसा हुआ। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं और कोमा में हैं। ब्रिटिश मीडिया द सन की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के हमले में घायल होने के बाद उन्हें तेहरान के सिना यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

>> (शेष पेज 04 पर)

एलपीजी संकट पर संसद में विपक्ष की नारेबाजी

वित्त मंत्री बोलीं- मुश्किल समय में साथ खड़े हों

हंगामा

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन, शुक्रवार को भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा- सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो यही एक्शन होगा। लोकसभा में हंगामे का कारण पहले 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इसके बाद दूसरी बार 2 बजे तक फिर से कार्यवाही स्थगित की गई। 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही भी केवल 1 घंटा चली। इसके बाद लोकसभा को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

इस दौरान विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेशों में हो रहे घटनाक्रम के कारण हमारे देश में कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सरकार जरूरी फंड मुहैया कराने और पूरी तरह तैयार रहने के लिए कदम उठा रही है।

>> (शेष पेज 04 पर)

फास्ट न्यूज

इंडिगो के एक विमान के लिए एवरेज 8 पायलट

नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को संसद में बताया कि इंडिगो में पायलट-टू-एयरक्राफ्ट रेश्यो 7.6 है यानी एक विमान के लिए एवरेज 8 पायलट हैं। ये देश की अन्य घरेलू एयर-लाइंस के मुकाबले सबसे कम है। यह जानकारी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लोकसभा में लिखित जवाब में दी। दरअसल एक विमान दिन-भर में कई उड़ानें करता है।

पंजाब में सिलेंडर उठाकर भाग रहे लोग

नई दिल्ली। अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देशभर में LPG की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लम्बी लाइनें हैं। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी भी हो रही है। कई जगहों पर 2 हजार का कॉमर्शियल सिलेंडर 4 हजार में बिक रहा है। वहीं पंजाब में लोग सिलेंडर लेकर भागते नजर आए। केरल में करीब 40% रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। उधर, दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LPG सप्लाई की बिगड़ी स्थिति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजस्थान में प्रदर्शन करते हुए सिलेंडर की शवयात्रा निकाली गई।

जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी

देहरादून/जयपु। पहाड़ी राज्यों में एकबार फिर बर्फबारी हो रही है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है। यहां स्नोफॉल के साथ बारिश का भी अलर्ट है। हिमाचल में 24 घंटे में तापमान 8°C कम हुआ। मनाली का तापमान 12.6°C रहा, इसमें 7°C की कमी आई। वहीं, सोलन में आज हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में बर्फबारी हुई है।

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर

ओडिशा से 8 विधायक बेंगलुरु भेजे, हरियाणा में लंच पर बुलाया

तमसा संकेत, एजेंसी

भुवनेश्वर। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। इसके चलते उसने ओडिशा और हरियाणा में अपने सभी विधायकों को बचाने के लिए रिजॉर्ट में रखने का फैसला किया है।

ओडिशा कांग्रेस के 8 विधायकों को बेंगलुरु भेजा गया है। जो दक्षिण बेंगलुरु के वंडरला रिजॉर्ट में ठहरे हैं। 4 विधायक विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए भुवनेश्वर में ही मौजूद हैं।

शनिवार सुबह तक चार और MLA बेंगलुरु पहुंच सकते हैं। राज्य में कांग्रेस के 12 विधायक हैं। इससे पहले चीफ व्हिप राजेन एक्का समेत 8 विधायक गुरुवार रात परिवार समेत बेंगलुरु पहुंच गए हैं।

उधर, हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों को लंच पर बुलाया। सूत्रों के मुताबिक इन विधायकों को 5 जोड़ी कपड़े साथ लाने कहा गया।

10 राज्यों की 37 सीटों को भरने के लिए 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' (राज्यसभा) के हर 2 साल में होने वाले चुनावों के लिए वोटिंग 16 मार्च को होनी है। वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे होगी। हरियाणा में हो रही हलचल के बीच दोपहर 1 बजे तक कांग्रेस के सभी 37 विधायक पहुंच गए।

कांग्रेस ने लागातार असम से झूठ बोला : पीएम

किसानों को विदेशों पर निर्भर रखा, दौरे के पहले दिन 24,250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन-शिलान्यास

- पीएम को स्मृति विह्न देकर असम सीएम ने सम्मानित किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने असम में 24,250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने संबोधित किया।

तमसा संकेत, एजेंसी

गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने असम के लोगों से लगातार झूठ बोला। कांग्रेस की गलत नीतियों ने इस राज्य को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि बाहरी देशों के युद्ध की वजह से हमारे किसानों पर असर पड़ता है। हमने कृषि को बाहरी संकट से बचाने के लिए आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दिया है। कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो किसी भी स्थिति देश के लिए ईमानदार नहीं है। मोदी ने कहा कि आज युद्ध की स्थिति में कांग्रेस केवल गलत प्रचार करने में जुटी है। वे केवल देश को अंधेरे में रखना चाहते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। पीएम ने चाय किसानें के लिए कहा... टी-गार्डन के किसानों का सम्मान करना मेरे लिए कर्ज चुकाने जैसा है। आपकी चाय बेचकर मैं पीएम बन गया। मां कामाख्या देवी ने मुझे चाय बागान के लोगों का कर्ज चुकाने का मौका दिया है। पीएम 13-14 अप्रैल को असम के दो दिन के दौर पर हैं। उन्होंने पहले दिन 24.250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए 3 नई ट्रेनों की शुरुआत भी की। पीएम दो दिन में यहां कुल मिलाकर 47800 रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 14 मार्च को सुबह करीब 10:45 बजे प्रधानमंत्री सिलचर में भूमि पूजन करेंगे और करीब 23,550 करोड़ रुपए के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे।

पीएम ने एक्स पर लिखा- राज्य की एनडीए सरकार तारीफ के काबिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में चाय किसानों को पट्टा वितरण को लेकर लिखा कि ये न्याय और सम्मान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम। मैं इसके लिए असम में NDA सरकार की तारीफ करता हूं। हमें चाय बागान परिवारों की मेहनत पर गर्व है और हम हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करेंगे।

संकट से बचाने के लिए आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दिया है। कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो किसी भी स्थिति देश के लिए ईमानदार नहीं है। मोदी ने कहा कि आज युद्ध की स्थिति में कांग्रेस केवल गलत प्रचार

हाइड्रो प्रोजेक्ट के उद्घाटन से क्षेत्र के लोगों को फायदा

पीएम के असम के दीमा हसाओ और वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिलों में मौजूद कोपिली हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देश को समर्पित करेंगे। 2,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बना यह प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी जेनरेशन को बढ़ाएगा, इलाके में ग्रिड स्टेबिलिटी में सुधार करेगा और घरों, किसानों और इंडस्ट्रीज़ को भरोसेमंद बिजली सप्लाई पक्का करेगा। प्रधानमंत्री ऑयल इंडिया लिमिटेड की नुमालीगढ़-सिलीगुड़ी प्रोडक्ट पाइपलाइन (NSPL) का कैपेसिटी बढ़ाने का प्रोजेक्ट देश को समर्पित करेंगे। यह प्रोजेक्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकालने में मदद करके नुमालीगढ़ रिफाइनरी को 3 MMTPA से 9 MMTPA तक बढ़ाने में मदद करेगा। इसमें लगभग 420 करोड़ रुपए की लागत से बनी रंगिया-मुरकोंगसेलेक रेल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन (558 km) और लगभग 1,180 करोड़ रुपये की लागत से बनी चपरमुख-डिब्रूगढ़ रेल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन (571 km) शामिल हैं।

रद : सीजेआई बोले- कानून बनाया तो महिलाओं को कोई काम नहीं देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा

पीरियड्स में पेड लीव की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को देशभर में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स में पेड लीव देने की मांग वाली याचिका खारिज हो गई।CJI सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में बनी रूढ़ियों को और मजबूत कर सकती हैं। यह कानून बनाया तो महिलाओं को कोई काम नहीं देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा। CJI ने कहा- ये याचिकाएं डर पैदा करने के लिए, महिलाओं को हीन दिखाने के लिए, यह जताने के लिए दायर की जाती हैं कि पीरियड्स उनके साथ होने वाली कोई बुरी चीज है। यह उनका पॉजिटिव राइट है, लेकिन उस नियोक्ता के बारे में सोचिए, जिसे पेड लीव देनी होगी। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान मेंस्ट्रुअल लीव को अनिवार्य बनाने के संभावित सामाजिक परिणामों के बारे में चिंता जाहिर की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस मामले को लेकर खुद कोई महिला कोर्ट में नहीं आई है। संविधान के अनुच्छेद 32 के साथ अनुच्छेद 14, 21 और अनुच्छेद 141 और 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कामकाजी महिलाओं और महिला छात्रों को अवकाश के रूप में राहत प्रदान करने के संबंध में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए निर्देश जारी करें। एडिनोमायोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज) से संबंधित समस्याओं को मान्यता देते हों और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अनुरूप छुट्टी देने समेत सभी जरूरी राहतें देते हों।

नई याचिका की मांगें...

- भारत सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे कानून/नीतियां/सरकारी आदेश लाने का निर्देश देना जो मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को होने वाली पीड़ा (डिसमेनोरिया, एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय फाइब्रॉइड, एडिनोमायोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज) से संबंधित समस्याओं को मान्यता देते हों और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अनुरूप छुट्टी देने समेत सभी जरूरी राहतें देते हों।
- संविधान के अनुच्छेद 32 के साथ अनुच्छेद 14, 21 और अनुच्छेद 141 और 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कामकाजी महिलाओं और महिला छात्रों को अवकाश के रूप में को दूर करने के लिए निर्देश जारी करें।

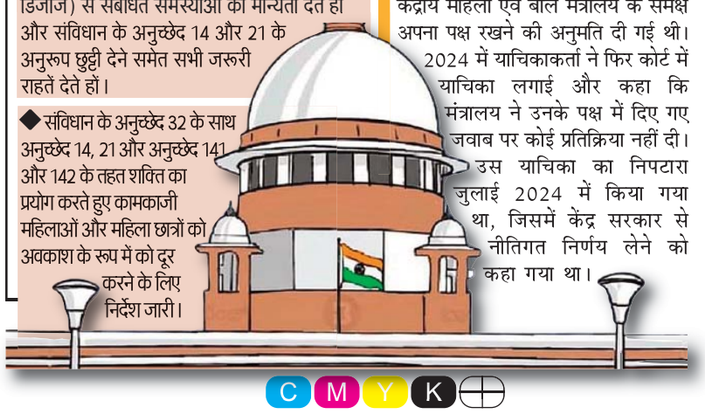

मेंस्ट्रुअल लीव का मुद्दा तीसरी बार कोर्ट लेकर पहुंचा याचिकाकर्ता

पेड मेंस्ट्रुअल लीव की याचिका लेकर शैलेंद्र मणि तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पहली याचिका का निपटारा फरवरी 2023 में किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को केंद्रीय महिला एवं बाल मंत्रालय के समक्ष अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गई थी। 2024 में याचिकाकर्ता ने फिर कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि मंत्रालय ने उनके पक्ष में दिए गए जवाब पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस याचिका का निपटारा जुलाई 2024 में किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार से नीतिगत निर्णय लेने को कहा गया था।

पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं, एलपीजी चिंता का विषय : सरकार

रोजाना 75.7 लाख सिलेंडर बुक हो रहे, ईरान जंग से पहले 55.7 लाख होते थे

बैठक

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद किए जाने के कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर दबाव बढ़ने के बीच भारत सरकार ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन अवग-अलग मंत्रालयों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से LPG हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार ने बताया कि ईरान जंग के कारण देश में गैस बुकिंग की संख्या में लगभग 20 लाख की बढ़ोतरी हुई है। सरकार की तरफ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी (मार्केटिंग एवं ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने बताया कि जंग से पहले हर रोज औसतन 55.7 लाख सिलेंडरों की बुकिंग होती थी। अभी एक दिन में लगभग 75.7 लाख गैस बुकिंग हो रही है। सरकार ने कहा कि जंग के माहौल के बीच LPG सिलेंडर की बुकिंग में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है।

>> (शेष पेज 04 पर)

पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा- लोगों को घबराने की जरूरत नहीं

पेट्रोलियम मंत्रालय ने आगे कहा- मौजूदा स्थिति में लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा बड़े शहरों और केंद्रों में व्यावसायिक उपभोक्ता जो फिलहाल LPG सप्लाई पर निर्भरता के कारण कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, भारत सरकार उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार के मुताबिक, भारत के पास कच्चे तेल के लिए 258 मिलियन मीट्रिक टन की रिफाइनिंग क्षमता है। सभी रिफाइनरियां इस समय 100% या उससे अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं।

सम्पादकीय

सरकार के हाथ मजबूत करे निजी क्षेत्र

जहां एक तरफ कई देशों में वृद्ध आबादी बढ़ती जा रही है और जापान तथा इटली जैसे देश घटती जन्म दर से जूझ रहे हैं, वहीं दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में कामकाजी उम्र के लोगों की जनसंख्या बरकरार है। आज भारत में दो-तिहाई लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। देश की सबसे बड़ी ताकत देश के युवा हैं। युवा संभावनाशील शक्ति बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जरूरत है इस ऊर्जा को सही दिशा देकर एक मजबूत आर्थिक ताकत में रूपांतरित किया जाए।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए गत दिनों संसद में पेश केंद्रीय बजट में युवाओं को सिर्फ 'भविष्य' नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें वर्तमान में 'भविष्य का निर्माणकर्ता' माना गया है। इन भविष्य के निर्माताओं को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि उनके लिए अवसरों की ऐसी सीढ़ी तैयार की जाए, जिससे वे अपनी रुचियों और कौशल का सही उपयोग कर नई ऊंचाइयां छू सकें। युवा जनसांख्यिकी के लिए पढ़ाई और रोजगार का ऐसा परिवेश तैयार करना होगा, जो उन्हीं की तरह विविध, बहुआयामी और गतिशील हो। जमीनी वास्तविकताओं और अंतर क्षेत्रीय जटिलताओं को समझते हुए सरकार ने बजट में प्रतिभाओं में निवेश को प्राथमिकता दी है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी योजनाएं शुरू की गईं, जिन्होंने चुनिंदा क्षेत्रों में प्रशिक्षण को उद्योग के साथ जोड़ा और इस साझेदारी से कौशल अंतर को पाटने की कोशिश की। बजट इन योजनाओं को और विस्तार तो देता ही है, साथ ही नए अवसरों की घोषणा भी करता है।

भारत की विशिष्टताओं को ध्यान में रख कर देखें तो बजट युवा-केंद्रित प्राथमिकताओं को उकेरता है। भारत की डिजिटल क्षमता उसकी पहली बड़ी ताकत है। भारत तेजी से मोबाइल-आधारित क्रिएटर इकोनमी बन रहा है। आज युवा सिर्फ कंटेंट देखना नहीं चाहते, वे कंटेंट बनाना भी चाहते हैं। डिजिटल क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए हमें डिजिटल माडल्स को सीखने पर जोर देना होगा। रचनात्मक क्षेत्रों में विकास को ध्यान में रख कर बजट में 15,000 स्कूलों और 500 कालेजों में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कामिक्स के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का प्रस्ताव है। इन लैब्स के जरिये युवा तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना सीखेंगे जिससे उनकी रचनात्मक आकांक्षाओं को सही औपचारिक स्वरूप मिलेगा और वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लायक कौशल विकसित कर पाएंगे। दूसरा अहम स्तंभ है उद्यमिता।

भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से छोटे शहरों और सुदूर क्षेत्रों तक विस्तार पा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के आवंटन में 62 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी इसका प्रमाण है कि सरकार भविष्य के लिए सही कौशल से लैस सक्रिय कार्यबल बनाने को लेकर गंभीर है।

बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों में इकोनमिक रीजन विकसित करने की बात कही गई है। उद्यमिता और आर्थिक विकास को साथ जोड़ते हुए बात ऐसे शहरों की हो रही है, जहां रोजगार के विकल्पों के साथ-साथ बेहतर जीवन की आशा भी है। घर के पास अच्छे अवसर मिलने से बड़े शहरों की तरफ युवाओं का पलायन कम होगा और देश में संतुलित विकास हो सकेगा। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है हमारे उच्च शिक्षा संस्थान, जो देश के लिए एक सशक्त भविष्य की नींव रख सकते हैं और जिनकी भूमिका आने वाले दिनों में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी।

एजुकेशन टू एंप्लायमेंट एंड एंटरप्राइज नामक एक स्थायी समिति बनाने का जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, जिससे केवल डिग्री प्राप्त नहीं होगी, बल्कि काम करने का कौशल भी विकसित होगा। साथ ही पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की योजना भी रखी गई है। ये टाउनशिप्स संपूर्ण शिक्षा का केंद्र होंगी, जिनमें विश्वविद्यालय, कालेज, शोध संस्थान और कौशल केंद्र, सबके लिए जगह होगी। बजट में टियर-2 और टियर-3 शहरों में इकोनमिक रीजन विकसित करने की बात कही गई है। उद्यमिता और आर्थिक विकास को साथ जोड़ते हुए बात ऐसे शहरों की हो रही है, जहां रोजगार के विकल्पों के साथ-साथ बेहतर जीवन की आशा भी है। घर के पास अच्छे अवसर मिलने से बड़े शहरों की तरफ युवाओं का पलायन कम होगा और देश में संतुलित विकास हो सकेगा।

ममता आर पार की लड़ाई के मूड में !

पिछले विधानसभा चुनाव में ममता ने खुद को धर्मनिष्ठ हिंदू के रूप में पेश करने के लिए मंच से चंडी मठ का पाठ किया था। इस बार भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वह चुनाव से पहले सिलीगुड़ी में दुर्गा आंगन और महाकाल मंदिर निर्माण की घोषणा करेंगी।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में जिस तरह पांच दिनों तक धरना देकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नौटंकी की। उसको अंततः बिना किसी ठोस परिणाम के ही समाप्त होना था और वही हुआ। यह धरना केवल एक राजनीतिक स्टंट भर नहीं था, बल्कि इसने राज्य की तृणमूल सरकार को भी सवालों के कठघरे में ला दिया है। पांच दिन तक चले इस धरने को तृणमूल कांग्रेस ने अचानक खत्म कर दिया तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। सवाल यह भी उठता है कि SIR को लेकर दिए इस धरने को बिना किसी परिणाम के ही खत्म करना था, तो फिर इतने दिन यह प्रपंच क्यों किया गया? दरअसल, ममता बनर्जी की अनावश्यक अड़ंगेबाजी के चलते लगातार हो रही देरी और राज्य सरकार तथा चुनाव आयोग के बीच टकराव ने एक नई बहस को जन्म दिया है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि यदि समय पर मतदाता सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया, तो विधानसभा चुनाव कराने में कठिनाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति शासन की संभावना को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि यह अभी केवल राजनीतिक चर्चा का विषय है, लेकिन इससे राज्य की राजनीति में अस्थिरता की झलक जरूर मिलती है। इस सब के बावजूद ममता चुप नहीं हो रही है । ताजा समाचारों के अनुसार भारत के इतिहास में यह पहली बार देखने को मिल रहा है, जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। विपक्ष ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर 193 सांसदों के साइन हो चुके हैं। संसद के किसी एक सदन में आज विपक्ष नोटिस दे सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ये प्रस्ताव लेकर आ रही हैं, जिसका कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां समर्थन कर रही हैं। आखिर, ममता बनर्जी क्यों मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ महाभियोग नोटिस ला रही हैं? दरअसल, पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले डेढ़ दशक से केवल सत्ता परिवर्तन या चुनावी संघर्ष की कहानी नहीं रही है। 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद राज्य की राजनीति एक ऐसे दौर में दाख़िल हुई, जहां राज्य सरकार, राज्यपाल, न्यायपालिका और केंद्र सभी के बीच संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे। इसी कारण ममता बनर्जी के शासनकाल में कई बार ऐसा माहौल बना जब यह प्रश्न राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? हालांकि अब तक यह आशंका कभी वास्तविकता में नहीं बदली, लेकिन इसके पीछे की परिस्थितियां और टकराव बंगाल की समकालीन राजनीति को समझने के लिए अहम हैं। फ़िलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक सलाहकार आई-पैक के कोलकाता कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे की कड़ी निंदा की। ममता बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख और तृणमूल कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारकर उनकी पार्टी के आंतरिक डेटा को जब्त करने की कोशिश कर रही है। जब ईडी ने कार्यालय पर छापा मारा तो ममता नाराज हो गईं। यह संभवतः पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री ने ईडी के छापे के विरोध में व्यक्तिगत रूप से किसी सलाहकार निकाय के कार्यालय का दौरा किया है। पार्टी के सांसदों ने दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों को इन आरोपों के खिलाफ विरोध करने का अधिकार होना चाहिए कि जांच तंत्र निष्पक्ष नहीं है; ईडी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को भी नोटिस जारी किया था, जिन्होंने उन्हें बिना किसी आक्रामकता के ईडी कार्यालय में आने की चुनौती दी थी।रॉबर्ट वाड्रा से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। उन्हें घंटों बैठाया गया; लेकिन उनमें से किसी ने भी आक्रामक तरीके से काम नहीं किया। इस पृष्ठभूमि में, यह ममता ही हैं जो सत्ता में होने के बाद भी मार्च निकालती हैं, जिसे तात्कालिकता की राजनीति कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि कांग्रेस पिछले पचास वर्षों में पहले की तरह सत्ता में नहीं आई है; लेकिन वामपंथियों ने कांग्रेस को सत्ता से छीन लिया और ममता ने वाम की सत्ता को चकनाचूर कर दिया। पिछले 15 वर्षों में, कांग्रेस और वाम कमजोर हो गए हैं और उनकी जगह भाजपा ने ले ली है। कांग्रेस अब शून्य पर है और 34 वर्षों तक शासन करने वाला वाम मोर्चा पिछले विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत सका। इसके विपरीत, भाजपा 41 प्रतिशत वोट और 77 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की संख्या 2019 की तुलना में कम थी। हालांकि, उनके 39 प्रतिशत वोट शेयर और 12 सीटें दर्शाती हैं कि उनके पास राज्य में तृणमूल कांग्रेस का एक मजबूत विकल्प है। ममता को शुरू में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट का समर्थन मिला था, जिसमें 29 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं। ममता यह जानते हुए कि वह अकेले मुस्लिम वोटों के आधार पर नहीं चुनी जा सकती हैं, उन्होंने हिंदू वोट के लिए तुष्टिकरण की राजनीति का सहारा लिया। इस साल के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के भाजपा के दावे को अतिशयोक्ति के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2021 का चुनाव उसी आत्मविश्वास के साथ लड़ा था, जो तृणमूल कांग्रेस से पीछे रह गया था। पश्चिम बंगाल में 2021 की तुलना में राजनीतिक माहौल काफी बदल गया है। पड़ोसी बांग्लादेश की घटनाओं ने पूरे देश को प्रभावित किया। प्रभावित। पश्चिम बंगाल में लगभग 29 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता तृणमूल कांग्रेस की ताकत हैं और भाजपा विरोधी, वामपंथी मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा तृणमूल कांग्रेस की ताकत है। सत्ता परिवर्तन तभी संभव है जब मुस्लिम वोट बैंक को झटका लगे या भाजपा के पक्ष में हिंदू वोट का व्यापक ध्रुवीकरण हो। पिछले कुछ वर्षों में, वाम मोर्चे और बाद में ममता बनर्जी सरकार के दौरान बांग्लादेश से घुसपैठ पश्चिम बंगाल के बाहर के घुसपैठियों के 24 परगना क्षेत्रों में वितरित आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र की घुसपैठ में पाई गई है यह साबित हो चुका है। हाल ही में शाह ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के चारों ओर घेराबंदी की जाएगी ताकि कोई घुसपैठिया अंदर न आ सके। सवाल यह है कि पिछले दस सालों में किसने उनके हाथ बांधे थे। लेकिन शाह घुसपैठियों को रोकने की कोशिश करने के बजाय सीमा पर बाड़ लगाने में ममता को चित्रित करने में अधिक रुचि रखते हैं। मुस्लिम वोटों को मजबूत करने की कोशिश में, ममता वही कदम उठाती दिख रही हैं।

अशोक भाटिया

चौथी कक्षा के छात्रों...

राजेश जैन

डिजिटल एजुकेशन के अगुआ देश लौट रहे किताबों की ओर

दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट ने जीवन के लगभग हर क्षेत्र को बदल दिया है। शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही। गत डेढ़ दशक में स्कूलों और विश्वविद्यालयों में टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन कंटेंट को आधुनिक शिक्षा का पर्याय मान लिया गया। यह माना गया कि अगर बच्चों को बचपन से ही डिजिटल माध्यमों से पढ़ाया जाएगा तो वे भविष्य की टेक्नोलॉजी आधारित दुनिया के लिए बेहतर तैयार होंगे। लेकिन अब एक दिलचस्प मोड़ सामने आ रहा है। जिस डिजिटल शिक्षा मॉडल को दुनिया भविष्य मान रही थी, वही मॉडल अब कई देशों में पुनर्मूल्यांकन के दौर से गुजर रहा है। दुनिया की सबसे अधिक डिजिटल शिक्षा प्रणालियों में गिने जाने वाले स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश फिर से किताब, कागज और पेन की ओर लौट रहे हैं। कई देशों में स्कूलों के भीतर मोबाइल फोन और टैबलेट के उपयोग को सीमित या प्रतिबंधित किया जा रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में सामने आए शोध, अनुभव और सीखने के परिणामों ने शिक्षा नीति निर्माताओं को सोचने पर मजबूर किया है। करीब 15 साल पहले दुनिया के कई विकसित देशों ने शिक्षा के डिजिटल भविष्य की परिकल्पना की। इस सोच के पीछे कई

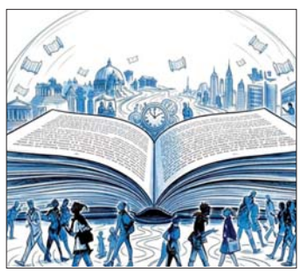

तर्क थे। पहला, तकनीक से पढ़ाई को अधिक रोचक और इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है। दूसरा, इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को वैश्विक ज्ञान तक तुरंत पहुंच मिल सकती है। तीसरा, डिजिटल उपकरणों के जरिए शिक्षा को अधिक व्यक्तिगत यानी पर्सनलाइज लर्निंग बनाया जा सकता है। स्वीडन उन देशों में था जिसने सबसे पहले स्कूलों में डिजिटल माध्यमों को बड़े पैमाने पर अपनाया। 2009 के आसपास वहां के स्कूलों में टैबलेट और कंप्यूटर को पाठ्यपुस्तकों का विकल्प बनाने की शुरुआत हुई। धीरे-धीरे कई स्कूलों में किताबों की जगह डिजिटल उपकरणों ने ले ली। स्मार्ट बोर्ड, ऑनलाइन सामग्री और डिजिटल असाइनमेंट को आधुनिक शिक्षा का प्रतीक माना जाने लगा। फिनलैंड, जो अपनी शिक्षा प्रणाली के लिए दुनिया में सबसे अधिक प्रशंसित देशों में से एक है, वहां भी स्कूलों में डिजिटल उपकरणों को बड़े उत्साह के साथ अपनाया गया। कई जगह छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए गए और पढ़ाई का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय यह मॉडल इतना आकर्षक लगा कि दुनिया के कई देशों ने इसे अपनाने की कोशिश की। भारत में भी डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट एजुकेशन जैसे शब्द शिक्षा सुधार के प्रमुख नारे बन गए। जब डिजिटल मॉडल पर उठने लगे सवाल लगभग एक दशक तक डिजिटल शिक्षा के प्रयोग के बाद कुछ समस्याएं धीरे-धीरे सामने आने लगीं। शिक्षकों, अभिभावकों और शोधकर्ताओं ने पाया कि तकनीक ने पढ़ाई को आसान तो बनाया है लेकिन कई बुनियादी कौशल कमजोर भी कर दिए हैं। स्वीडन में किए गए अध्ययनों में पाया गया कि स्क्रीन पर पढ़ने वाले छात्रों की एकाग्रता और गहराई से समझने की क्षमता कम हो रही है। चौथी कक्षा के छात्रों की पढ़ने की क्षमता का आकलन करने वाले अंतरराष्ट्रीय अध्ययन प्रोग्रेस इन इंटरनेशनल रीडिंग लिटरेसी स्टडी में 2016 और 2021 के बीच स्वीडन के बच्चों के पढ़ने के स्कोर में गिरावट दर्ज की गई। शिक्षाविदों ने देखा कि जब बच्चे टैबलेट या लैपटॉप पर पढ़ते हैं तो उनका ध्यान जल्दी भटकता है। एक क्लिक में गेम, सोशल मीडिया या अन्य वेबसाइटों तक पहुंच उन्हें पढ़ाई से दूर कर देती है। डिजिटल उपकरण पढ़ाई के साथ-साथ मनोरंजन का भी माध्यम हैं, इसलिए उनमें विचलन की संभावना अधिक होती है। फिनलैंड के शिक्षकों ने भी यही अनुभव साझा किया कई शिक्षकों ने बताया कि डिजिटल उपकरणों के कारण छात्रों का ध्यान बार-बार भटक जाता है। बच्चे असाइनमेंट जल्दी खत्म कर लेते हैं ताकि वे गेम खेल सकें या सोशल मीडिया पर जा सकें। डिजिटल शिक्षा पर सवाल उठने के पीछे सबसे बड़ा कारण बच्चों के मस्तिष्क और व्यवहार पर स्क्रीन के प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंता है। नॉर्वे और अमेरिका के कई शोध बताते हैं कि जब बच्चे हाथ से लिखते हैं तो उनके मस्तिष्क के कई हिस्से एक साथ सक्रिय होते हैं। अक्षर बनाने की प्रक्रिया, उंगलियों का दबाव और लिखावट की संरचना दिमाग में मजबूत स्मृति चिन्ह (मेमोरी ट्रेस) बनाते हैं। इसके विपरीत, कीबोर्ड पर टाइपिंग अपेक्षाकृत एक यांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें मस्तिष्क जानकारी को उतनी गहराई से प्रोसेस नहीं करता। यही कारण है कि हाथ से नोट्स लिखने वाले छात्र विषयों को अधिक गहराई से समझते हैं। इसके अलावा लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर तनाव, नींद की समस्या और मानसिक बेचैनी भी बढ़ने की आशंका रहती है। फिनलैंड के कुछ अध्ययन बताते हैं कि किशोर औसतन प्रतिदिन लगभग छह घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए चिंताजनक है।

बीते 13 वर्षों...

डॉ. रमेश ठाकुर

भारतीय सभ्यता में 'इच्छामृत्यु' सदैव अस्वीकार?

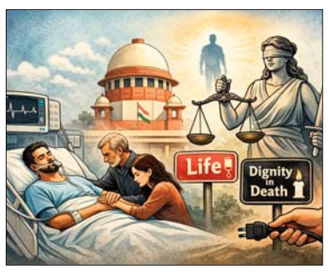

इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली समहति देकर जनमानस में नई किस्म की बहस को जन्म दे दिया है। बहस ऐसी है जिसमें सिर्फ भावनाओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। गाजियाबाद निवासी 32 वर्षीय हरीश राणा की इच्छामृत्यु पर दिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक ऐसा भावनात्मक फैसला है जो भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में पहली मर्तबा लिया गया। कोर्ट के आदेशानुसार इच्छा मृत्यु पर सभी प्रक्रियाएं बेशक मानवीय ढंग से और चिकित्सीय निगरान में होंगी लेकिन फैसला देने वाली पीठ के जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन खुद भी भावुक हो गए। उन्होंने स्वीकारा कि ये निर्णय देना उनके लिए बहुत कठिन था पर उन्हें अपने फैसले के जरिए एक व्यक्ति को उनके निष्क्रिय शरीर से होती अंतन पीड़ा से मुक्ति भी दिलवाना था जिसका उन्होंने कानूनी मर्यादयों में रहकर अपना फर्ज निभाया। ये मामला अगस्त 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था लेकिन यहां भी जजों की एकमत राय नहीं थी। काफी विमर्श के बाद शीर्ष कोर्ट ने 'मेडिकल बोर्ड' को गठित' करने का आदेश दिया। बोर्ड की जब रिपोर्ट पहुंची जिसमें चिकित्सकों ने बताया कि हरीश का शरीर शत-प्रतिशत निष्क्रिय हो चुका है इसलिए वह इच्छामृत्यु का हकदार है। फिलहाल, इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने जीवन के असमय अंत की चाहत पर समकालीन स्वास्थ्य देखभाल में ऐसी प्रथाओं की भूमिका पर अनोखी बहस को छेड़ा है जिसकी चर्चा लंबे समय तक होगी। यह बहस सभ्य समाज के कानूनी, नैतिक, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जटिलताओं और गतिशील पहलुओं को भी सोचने पर विवश करेगी। गौरतलब है, इच्छामृत्यु शब्द की उत्पत्ति भारत में नहीं, ग्रीस में हुई थी जिसका अर्थ होता है एक सुखद मृत्यु? कानून में जीवन का अधिकार' अनुच्छेद 21 में निहित है जो एक प्राकृतिक अधिकार भी लेकिन आत्महत्या जीवन का अप्राकृतिक अंत है और इसलिए 'जीवन के अधिकार' की अवधारणा के साथ असंगत और विरोधाभासी भी है। भारत में आत्महत्या गैरकानूनी होने के बावजूद भी नहीं रूकती लेकिन इच्छामृत्यु का नाम सुनकर न सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं बल्कि भावनाओं का समुद्र हिचकौले मारने लगता है। समूचे विश्व में भारतीय सभ्यता सदैव से उदारवादी मानी गई है। इस लिहाज से कोई भी व्यक्ति किसी को मरने के लिए नहीं बोल सकता? लेकिन हरीश राणा का मामला सबसे इतर है। बीते 13 वर्षों से उनके दर्द भरे जीवन को और लंबा खींचा जा रहा है। हरीश को विरह भरे जीवन से मुक्ति दिलवाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं? शीर्ष अदालत ने हरीश के शरीर से जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दे दी है जिसे चिकित्सकीय निगरानी में उनकी अंतिम सांसों को प्राकृतिक बनाया जाएगा। बेशक ये निर्णय पहला है पर आखिरी हो? आखिरी इसलिए, अगर इच्छा मृत्यु पर निर्णय देने का सिलसिला आगे भी चला तो इसके दुरुपयोग होने लगेंगे क्योंकि समाज में नैतिकता और न्याय का पतन तेजी से जारी है।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

जयसिंह रावत

आखिर उत्तराखण्ड की राजधानी है कहां ?

चमोली जिले में स्थित भराड़ीसैण (गैरसैण) में जब भी दो - तीन दिनों के लिये उत्तराखण्ड विधानसभा का सत्र चलता है तो सीमान्त हिमालयी प्रदेश उत्तराखण्ड की स्थाई राजधानी का मुद्दा फिर गरमा जाता है। नवम्बर 2000 से लेकर अब तक राज्य गठन के 25 साल हो गये लेकिन राज्य की राजधानी का मुद्दा अभी तक न तो सुलझ पाया और न ही निकट भविष्य में सुलझने के आसार नजर आ रहे हैं। भाजपा की सरकार ने राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिये भराड़ीसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दिया मगर विपक्षी राजनीतिक दल तो रहे दूर यह घोषणा राज्य की मांग को लेकर एक अभूतपूर्व आन्दोलन चलाने वाले लागों के गले भी नहीं उतरी। उतरती भी कैसे ? किसी एक स्थान पर महज कुछ दिन विधानसभा सत्र आहूत करने से वह स्थान राजधानी नहीं हो जाता! अगर लोग भराड़ीसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी मान भी लें तो शीतकालीन या स्थाई राजधानी का जवाब अनुत्तरित है। जिस भराड़ीसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है वहां छह साल में केवल एक बार ग्रीष्मकालीन सत्र हुआ और वह भी बहुत संक्षिप्त। नवम्बर 2000 में बने तीन नये राज्यों में से उत्तराखण्ड अकेला राज्य है जिसकी राजधानी आज तक तय नहीं हो पायी। इसके लिये कोई और नहीं बल्कि उत्तराखण्ड का अपना राजनीतिक तंत्र जिम्मेदार रहा है जो कि राज्य गठन से लेकर अब तक राजधानी को लेकर एक राय नहीं हो सका। जब संसद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पास हो गया था तो उसी समय से राजधानी की तलाश शुरू हो गयी थी लेकिन उस समय जब विधायकों और सांसदों में राजधानी को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं के बीच रस्साकस्सी होने लगी तो तत्कालीन बाजपेयी सरकार ने यह मुद्दा उत्तराखण्ड के लागों पर ही छोड़ दिया और तात्कालिक ढांचागत सुविधाओं को देखते हुये देहरादून को अस्थाई राजधानी घोषित करने के साथ ही कुमाऊं के लोगों को संतुष्ट करने के लिये नैनीताल को हाइकोर्ट दे दिया। आज ये दोनों शहर अपनी सीमित धारण क्षमता के कारण राजधानी और हाइकोर्ट के बोझ तले कुचले जा रहे हैं। दोनों ही भूगर्भीय दृष्टि से अति संवेदनशील है। नैनीताल की विकट स्थिति को देखते हुये स्वयं हाइकोर्ट को अपने लिये कोई नयी जगह तलाशने के आदेश देने पड़े। चूंकि केन्द्र सरकार ने राजधानी के चयन की जिम्मेदारी स्वयं उत्तराखण्ड (उत्तरांचल) सरकार पर छोड़ी हुयी थी इसलिये पहली नित्यानन्द स्वामी सरकार ने इसके लिये दीक्षित आयोग का गठन कर डाला जिसे 6 माह के अन्दर अपनी सिफारिश देनी थी लेकिन आयोग उत्तराखण्ड की राजनीति से अपरिचित नहीं था, इसलिये उसने मामला 8 साल तक लटकाये रखा। सरकारें आती रहीं-जाती भी रहीं मगर दीक्षित आयोग कायम रहा। 11 जनवरी 2001 को गठित इस आयोग ने भारी जन दबाव के बाद 17 अगस्त 2008 को अपनी रिपोर्ट दाखिल की जो कि दिसम्बर 2008 में विधानसभा में रखी गयी। रिपोर्ट भी खोदा पहाड़ निली चुहिया जैसी ही थी। दीक्षित आयोग की यह रिपोर्ट भी उत्तराखण्ड की क्षेत्रवादी राजनीति की पोल खोलने के लिये काफी है। आयोग के समक्ष 70 विधायकों में से एक और पांच सांसदों में से भी एक ने अपनी राय दी। दिलचस्प बात यह है कि सर्वेक्षणों में जनता का भारी बहुमत गैरसैण के पक्ष में था लेकिन आयोग के समक्ष लिखित राय देने वाले मात्र 4-5 लोग ही इसके पक्ष में खड़े दिखे। आयोग में राय देने वाले अधिकांश लोगों ने राज्य हित के बजाय अपने क्षेत्रीय हित को प्राथमिकता दी। गढ़वाल के लोगों ने ऋषिकेश या देहरादून और कुमाऊं के लोगों ने रामनगर या काशीपुर को वरीयता दी। ऐसी स्थिति में आयोग ने देहरादून के रायपुर क्षेत्र को ही अपनी वरीयता दे डाली। राजधानी को लेकर सबसे बड़ा मजाक तो तब हुआ जब भराड़ीसैण में आयोजित बजट सत्र के दौरान 4 मार्च 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषण हो गयी। इस घोषणा की पुष्टि के लिये 8 जून 2020 को अधिकारिक अधिसूचना भी जारी हो गयी। इसकी वास्तविकता भी जानिये ! भराड़ीसैण के 'ग्रीष्मकालीन राजधानी' बनने के बाद पिछले छह वर्षों में केवल जून 2022 में ही वहां वास्तविक ग्रीष्मकालीन सत्र हुआ। शेष वर्षों में कोरोना, चुनाव, चारधाम यात्रा या ठंड के बहानों के बीच ग्रीष्मकालीन राजधानी में गर्मियों के सत्र सिरे ही नहीं चढ़े। एक दो सत्र शीतकाल में चले भी तो आधे अधूरे! राजधानी वह होती है जहां से शासन प्रशासन चलता है। जहां मंत्रियों से लेकर सचिवों के कार्यालय चलते हैं ताकि लोगों को देहरादून आने के बजाय भराड़ीसैण में ही अपनी समस्याओं का निदान और विकास की मांग पूरी हो जाय। एक सप्ताह तक विधानसभा चलाना राजधानी चलाना नहीं होता। संक्षिप्त सत्र पर ही करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं और जनता से लेकर कर्मचारियों तक को होने वाली असुविधा अलग होती है। अब तों जम्मू कश्मीर की दो राजधानियों को भी एक बना दिया, जबकि वह डेढ सौ साल से भी पुरानी व्यवस्था थी। ताजा आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखण्ड में 25 वर्षों के दौरान 80 हजार करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है। इस बार एक लाख करोड़ से अधिक का बजट प्रस्तावित है जिसमें राज्य का अपना राजस्व बहुत कम है। देखा जाय तो यह केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास का संभवतः सबसे लंबा 'राजनीतिक छलावा है। चलो भराड़ीसैण को ग्रीष्मकालीन राजधानी मान लिया तो शीतकालीन राजधानी कहां है? इसका उत्तर भी इसलिये गुम हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस और उत्तराखण्ड क्रांति दल जैसे दल भराड़ीसैण को राजधानी बनाने की घोषणा कर चुके हैं हालांकि कांग्रेस दो बार सत्ता में रह चुकी है और उत्तराखण्ड क्रांति दल भी सरकारों में शामिल रहा है। ऐसी स्थिति में देहरादून को स्थाई या शीतकालीन राजधानी घोषित करना राजनीतिक दृष्टि से जोखिम से खाली नहीं है। देखा जाय तो राजधानी केवल ईंट-पत्थर की इमारतों या विधानसभा की सीढ़ियों का नाम नहीं है। यह राज्य के 'विजन' और उसकी 'आत्मा' का प्रतिबिंब होती है। 25 साल बाद भी यदि उत्तराखंड की सरकारें 'ग्रीष्मकालीन' और 'शीतकालीन' के जुमलों में उलझी हैं, तो यह उन शहीदों के बलिदान का अपमान है जिन्होंने एक समृद्ध और स्वाभिमानी पहाड़ के लिए अपना रक्त दिया था। नये राज्य की मांग और उसके गठन का आधार भौगालिक स्थिति और सांस्कृतिक पहचान थी। लेकिन राजधानी के कारण यह हिमालयी राज्य अपनी सांस्कृतिक पहचान भी खोता जा रहा है। यदि भराड़ीसैण को राजधानी बनाना है तो वहां केवल सत्र नहीं, बल्कि 'शासन' होना चाहिए और यदि देहरादून ही स्थायी ठिकाना है तो फिर 'अस्थायी' का ढोंग बंद कर पहाड़ों के विकास के लिए कोई वैकल्पिक मॉडल पेश किया जाना चाहिए।

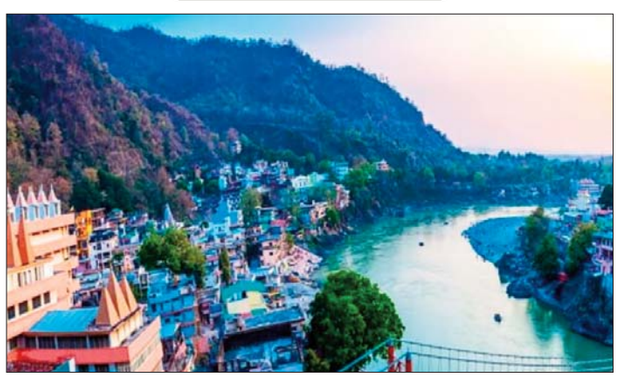

ईरानी टीम का अमेरिका न आना ही बेहतर : ट्रम्प

हालांकि हम उनका स्वागत करेंगे, ईरानी मंत्री बोल चुके-फीफा वर्ल्ड कप खेलना मुश्किल

मुंबई, एजेंसी

अमेरिका में होने जा रहे 2026 फीफा वर्ल्ड कप से पहले सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को लेकर एक बयान दिया है, जिसने खेल और कूटनीति दोनों क्षेत्रों में हलचल पैदा कर दी है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ईरानी टीम को अपनी सुरक्षा और जान-माल का ध्यान रखते हुए अमेरिका आने के फैसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका मेजबान देश होने के नाते सभी टीमों का स्वागत करेगा और ईरानी टीम के लिए भी दरवाजे खुले हैं। दरअसल, 2026 का FIFA World Cup 2026 तीन देशों—United States, Canada और Mexico—की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। यह पहला

मौका होगा जब विश्व कप तीन देशों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून 2026 को Mexico City में उद्घाटन मैच के साथ होगी। वहीं इसका फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को MetLife Stadium में खेला जाएगा। इस स्टेडियम को न्यूयॉर्क क्षेत्र के प्रमुख खेल स्थलों में गिना जाता है। अधिकारियों के अनुसार, खिलाड़ियों, टीम स्टाफ और दुनियाभर से आने वाले लाखों प्रशंसकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती, आधुनिक निगरानी व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय किया जा रहा है।

ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने सुरक्षा पर उठाए सवाल

ईरान फुटबॉल फेडरेशन (FFIRI) के अध्यक्ष मेहदी ताज ने भी वर्ल्ड कप को लेकर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि हालिया हमलों के बाद ईरान से वर्ल्ड कप को लेकर उम्मीद रखने की गुंजाइश नहीं है। ताज ने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर सवाल उठाते हुए कहा, ' वर्ल्ड कप का माहौल ऐसा ही रहने वाला है, तो कौन सा देश अपनी नेशनल टीम को ऐसी जगह भेजने की हिम्मत करेगा?'

पहली बार टूर्नामेंट में 104 मैच खेले जाएंगे

2026 का फीफा वर्ल्ड कप कई मायनों में खास होने वाला है। इस बार टूर्नामेंट में कुल 104 मैच खेले जाएंगे। पहली बार तीन देश मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। अमेरिका के कई बड़े शहरों में मैच आयोजित किए जाएंगे।

टिकटों की डिमांड सबसे ज्यादा, खिलाड़ियों को मिलेगा 'स्टार' ट्रीटमेंट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में ट्रम्प ने बताया कि वर्ल्ड कप के टिकटों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने फैन्स और खिलाड़ियों को भरोसा दिलाते हुए लिखा,'संयुक्त राज्य अमेरिका फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। टिकटों की बिक्री आसमान छू रही है। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे महान और सुरक्षित आयोजन होगा। सभी खिलाड़ियों, अधिकारियों और फैन्स के साथ 'सितारों' जैसा व्यवहार किया जाएगा।'

ईरानी खेल मंत्री ने कहा था कि खेलना मुश्किल

वहीं, एक दिन पहले ईरान के खेल मंत्री अहमद दुन्यामाली ने कहा कि देश की फुटबॉल टीम 2026 फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सकती। उनका कहना है कि अमेरिकी-इजराइली हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद बने हालात में टीम का टूर्नामेंट में भाग लेना संभव नहीं है। इससे पहले फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैन्टिनो ने बताया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि ईरान की राष्ट्रीय टीम को 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका आने की अनुमति दी जाएगी।

ज्वेरेव पहली बार इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में

एटीपी मास्टर्स के सभी 9 इवेंट्स में आखिरी-4 खेलने वाले पांचवें खिलाड़ी बने

नई दिल्ली, एजेंसी

जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने गुरुवार को इंडियन वेल्स मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में आर्थर फिल्स को 6-2, 6-3 से हराया। इस जीत के साथ ज्वेरेव ATP मास्टर्स-1000 के सभी नौ टूर्नामेंट में सेमीफाइनल खेलने वाले सिर्फ पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और एंडी मरे यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इस उपलब्धि के साथ ज्वेरेव 'बिग फोर' यानी रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और एंडी मरे के चुनिंदा खिलाड़ी क्लब में शामिल हो गए हैं। ज्वेरेव ने कहा,'इतिहास में ऐसा करने वाले सिर्फ पांच खिलाड़ियों में शामिल होना मेरे लिए बहुत खास है। यह ऐसी उपलब्धि है जिस पर मुझे गर्व है।' ज्वेरेव अब तक नौ में से पांच मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीत चुके हैं।

हालांकि, वह अभी तक कोई ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीत पाए हैं, जबकि तीन बार फाइनल तक पहुंच चुके हैं। टेनिस में ग्रैंड स्लैम के बाद मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। एक साल में कुल 9 ऐसे टूर्नामेंट होते हैं-इंडियन वेल्स, मियामी, मोंटे कार्लो, मैड्रिड, रोम, कनाडा, सिनसिनाटी, शंघाई और पेरिस। इन सभी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंचना किसी खिलाड़ी की निरंतरता और उच्च स्तर के प्रदर्शन को दर्शाता है। ज्वेरेव ने इंडियन वेल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना यह 'सेट' पूरा कर लिया है।

फास्ट न्यूज

यूट्यूबर अनुराग डोभाल की सेहत में सुधार

मुंबई। UK07 राइडर नाम से फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल की हालत में सुधार है। दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हुए कार एक्सीडेंट के बाद अब उन्हें ICU से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। अनुराग के मैनेजर और उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर हेल्थ अपडेट शेयर किया है। बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट रह चुके राइडर अनुराग डोभाल ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

हरियाणा महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए सिंगर बादशाह

पानीपत। बॉलीवुड सिंगर-रैपर बादशाह हरियाणा महिला आयोग के समन पर शुक्रवार को पेश नहीं हुए। उनकी तरफ पेश हुए वकीलों ने दलील दी कि किसी प्रोफेशनल कमिटमेंट में व्यस्त होने की वजह से बादशाह नहीं आ सके। आयोग से आगे का टाइम मांगा गया। इस पर महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया मीटिंग में ही भड़क गई। उन्होंने चेतावनी दी- बादशाह अगर 3 बजे तक पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। टटीरी सॉन्ग के आपत्तिजनक लिरिक्स और लड़कियों के शॉट्स को लेकर महिला आयोग ने उन्हें 6 मार्च को नोटिस भेजकर पानीपत SP ऑफिस में पेश होने के लिए कहा था। हालांकि बादशाह के वकील ने सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखन की परमिशन मांगी थी।

सऊदी अरब को दिया पूरा समर्थन

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक विशेष बैठक की। यह मुलाकात जेद्दा में हुई। इस दौरान शहबाज शरीफ ने पश्चिम एशिया के मौजूदा चुनौतीपूर्ण हालात में सऊदी अरब के लिए अपनी पूरी एकजुटता और समर्थन दिखाया। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमलों के बाद क्षेत्र में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

सूरज बड़जात्या की बेटी ईशा के रिसेप्शन में पहुंचे सलमान

आमिर खान भी नजर आए, तब्बू और रानी मुखर्जी भी इवेंट में शामिल हुईं

- सलमान खान रॉयल ब्लू शर्ट और सूट में कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे।
- जैकी श्रॉफ ब्लू आउटफिट और आइकॉनिक प्लांट नेकपीस के साथ पहुंचे।

मुंबई, एजेंसी

फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या ने गुरुवार शाम को मुंबई में अपनी बेटी ईशा और उनके पति अभिषेक की शादी का रिसेप्शन होस्ट किया। यह इवेंट जुहू के JW मैरियट होटल में हुआ और इसमें सलमान खान, आमिर खान समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए। सूरज बड़जात्या की बेटी के रिसेप्शन में विक्की कौशल, अनिल कपूर, अनुपम खेर, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीना गुप्ता और बोमन ईरानी जैसे कलाकार पहुंचे। इसके अलावा रानी मुखर्जी, सोनू सूद और जैकी श्रॉफ जैसे सेलेब्स भी नजर आए। बता दें कि सूरज बड़जात्या मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीनराइटर हैं। वे राजश्री प्रोडक्शंस के चेयरमैन हैं, जिसे उनके दादा ताराचंद बड़जात्या ने शुरू किया था। सूरज ने 1989 में 24 साल की उम्र में फिल्म मैंने प्यार किया से डायरेक्शन में डेब्यू किया था, जो बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। बता दें कि फिल्म मैंने प्यार किया बतौर लीड एक्टर सलमान खान की पहली फिल्म थी। उन्होंने 'हम आपके हैं कौन...!', 'हम साथ-साथ हैं', 'विवाह', 'प्रेम रतन धन पायो' और 'ऊंचाई' जैसी फिल्में बनाईं। उनकी फिल्मों में पारिवारिक रिश्ते, भारतीय परंपराएं और मूल्य खास तौर पर दिखाए जाते हैं।

बेटी के साथ दुबई में फंसीं लारा दत्ता भारत लौटीं

बोलीं- वीडियो इसलिए पोस्ट किया, क्योंकि वह मेरा आखिरी वीडियो हो सकता था

- लारा दत्ता ने 2011 में टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति से शादी की। दोनों की बेटी सायरा का जन्म 20 जनवरी 2012 को हुआ था।

मुंबई, एजेंसी

मध्य-पूर्व में चल रहे तनाव के बीच दुबई में फंसीं एक्ट्रेस लारा दत्ता और उनकी 14 साल की बेटी सुरक्षित मुंबई लौट आई हैं। लारा ने बताया कि दुबई के जेबेल अली पोर्ट के पास बमबारी के कारण स्थिति चिंताजनक थी। साथ ही एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो इसलिए पोस्ट किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह उनका आखिरी मैसेज भी हो सकता था। बता दें कि लारा दत्ता ने 4 मार्च को इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट कर दुबई में अपनी बेटी सायरा के साथ फंसे होने का अनुभव शेयर किया था। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में लारा दत्ता ने हाल ही में बताया कि उनका घर जेबेल अली पोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जहां लगातार बमबारी हो रही थी। उन्होंने कहा कि परिवार के पास लौटने के लिए उन्होंने

जोखिम उठाने का फैसला किया। लारा ने बताया कि वे दो घंटे की यात्रा करके फुजैराह पहुंचीं। इससे एक दिन पहले ही फुजैराह पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ था।

"लारा ने बताया कि मजाक में उन्होंने फिल्म वेलकम टू द जंगल में अपने को-स्टार अक्षय कुमार से कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था, जैसे वह फिल्म एयरलिफ्ट 2 का हिस्सा हों। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो एक निजी कारण से शेयर किया था। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी के साथ अकेले एक जोखिम भरी यात्रा पर निकलने वाली थीं और उस समय स्थिति को लेकर काफी अनिश्चितता थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मन में यह भी ख्याल आया कि शायद यह वीडियो आखिरी मैसेज हो सकता है।"

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए

महिलाओं-बच्चे समेत 4 लोगों की मौत, 15 घायल, तालिबान बोला- इसका जवाब देंगे

इस्लामाबाद, एजेंसी

पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमले किए। रॉयटर्स के मुताबिक, काबुल में घरों पर हुई बमबारी में 4 लोगों की मौत और 15 घायल हो गए। इसमें महिलाएं और बच्चे शामिल है। हमलों में कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं, तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक, यह हमला प्राइवेट एयरलाइन 'काम एयर' के फ्यूल डिपो पर किया गया, जो सिविलियन विमानों और UN के विमानों को भी फ्यूल सप्लाई करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि यह कार्रवाई पाकिस्तानी तालिबान (TTP) के ठिकानों पर की गई है। पाकिस्तान का कहना है कि हाल के महीनों में देश में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया दरअसल, पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव बनाता

रहा है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को न करने दे। इस्लामाबाद का आरोप है कि TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही है। पिछले कुछ हफ्तों में अफगान और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच सीमा पर कई बार झड़पें हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान मिशन (UNAMA) के अनुसार 26 फरवरी से 5 मार्च के बीच पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों में 56 नागरिक मारे गए हैं। इनमें 24 बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक इन हमलों के कारण करीब 1.15 लाख लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हुए हैं।

पाकिस्तान ने तालिबान नेताओं के गढ़ को निशाना बनाया

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि पाकिस्तानी हमले कंधार और पक्तिका प्रांतों में भी किए गए। कंधार तालिबान नेताओं का गढ़ माना जाता है। वहीं, तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ हमलों के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात

पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयरस्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलाल चौधरी ने दावा किया था कि सीमावर्ती इलाकों में TTP के ठिकानों पर कार्रवाई में कम से कम 70 लड़ाके मारे गए। बाद में पाकिस्तानी अखबार डॉन ने यह संख्या 80 तक पहुंचने का दावा किया था।

अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान को 'सही समय पर कड़ा जवाब' दिया जाएगा। मंत्रालय ने इन हमलों को देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ हमले को 'गजब लिल हक' ऑपरेशन नाम दिया था और काबुल समेत कई प्रांतों में हमले किए। 'गजब लिल हक' का मतलब है, अपने हक के लिए खड़े होना।

अमेरिका ने एच-1बी वीजा देने की प्रक्रिया में बदलाव किया

अब सैलरी के आधार पर होगा चयन, 1 अप्रैल से नया फार्म क 129 लागू होगा

नई दिल्ली, एजेंसी

अमेरिका ने एच-1बी वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थियों का चयन रैंडम लॉटरी के बजाय वेतन के आधार पर होगा। इसके लिए अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ने फॉर्म I-129 का नया सिस्टम बनाया है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों के लिए दाखिल याचिका में नौकरी से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इससे पहले की तुलना में ज्यादा अनुभवी और हाई सैलरी पाने वाले प्रोफेशनल्स को वीजा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नए सिस्टम में आवेदकों को चार वेतन स्तरों में बांटा जाएगा। जिस पद का वेतन स्तर जितना ऊंचा होगा, चयन प्रक्रिया में उसे उतने अधिक मौके मिलेंगे। मसलन, लेवल-4 के उम्मीदवार को चार मौके मिलेंगे, जबकि लेवल-1 को सिर्फ एक मौका मिलेगा। फॉर्म I-129 का उपयोग अस्थायी कामगारों को अमेरिका बुलाने के लिए किया जाता है। अमेरिका का श्रम

विभाग हर पेशे और शहर के लिए एक मानक वेतन तय करता है। उसी के आधार पर नौकरी को लेवल-1 से लेवल-4 में रखा जाता है। ट्रम्प के आदेश का क्या असर- भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हर साल कुल जारी किए जाने वाले एच-1बी वीजा में से 70% भारतीय प्रोफेशनल्स को जारी किए जाते हैं। एच-1 बी वीजा की फीस कितनी-पहले फीस लगभग 9 हजार डॉलर यानी करीब 8 लाख 30 हजार रुपए थी, लेकिन सितंबर 2025 में ट्रम्प ने इसे बढ़ाकर 1 लाथ डॉलर यानी लगभग 90 लाख रुपए कर दिया।इस वीजा की अवधि कितनी है-3-3 साल के लिए दो बार जारी होता है।

सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की इजाजत

अमेरिका ने 30 दिन की छूट दी, ईरान ने क्रूड ऑयल 200 डॉलर पहुंचने की चेतावनी दी थी

नई दिल्ली, एजेंसी

अमेरिका-इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 100 डॉलर के पार चली गई हैं। इसे काबू में करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने दूसरे देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अस्थाई मंजूरी दे दी है। रूस के कई ऑयल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी। हालांकि, इस पर भारतीय अधिकारी कह चुके हैं कि भारत तेल खरीदने के लिए किसी भी देश की इजाजत पर निर्भर नहीं है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग (वित्त मंत्रालय) ने गुरुवार को एक लाइसेंस जारी किया। इसके तहत उन रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिलीवरी और बिक्री की जा सकती है, जो 12 मार्च की रात 12:01 बजे से पहले जहाजों पर लोड हो चुके थे। यह छूट सिर्फ 11 अप्रैल तक के लिए दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने

बताया कि इसका मकसद दुनियाभर में तेल की सप्लाई बढ़ाना है, ताकि बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके। जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो पश्चिमी देशों का मानना था कि युद्ध के लिए पैसा रूस को तेल और गैस बेचकर मिल रहा है। इसी 'फंडिंग' को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगानी शुरू की थी। मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाल ही में हुए हमलों के बाद फिर से कच्चे तेल की कीमतों में 9% से ज्यादा की तेजी आई है। इस उछाल के साथ ही तेल का दाम एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार हो गया है।

अमेरिका ने कहा- रूस को ज्यादा फायदा नहीं होगा

अमेरिका के ट्रेजरी मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रम्प वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक शॉर्ट-टर्म फैसला है और इससे रूस को कोई बहुत बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा। बेसेंट के मुताबिक रूस की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल निकालने के वक्त लगने वाले टैक्स से आता है, जबकि यह छूट सिर्फ उस तेल के लिए है, जो पहले से ही ट्रांजिट (रास्ते) में है।

क्यों बदला अमेरिका का मन? 3 मुख्य वजहें

1. होर्मुज रूट से सप्लाई ठप: ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जंग से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में सप्लाई ठप हो गई है। यहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। भारत जैसे देश अपनी जरूरत का करीब आधा तेल इसी रास्ते से मंगाते हैं।

2. 200 डॉलर पहुंच सकता है कच्चा तेल: पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई थीं। ईरान ने चेतावनी दी है कि कीमतें 200 डॉलर तक पहुंच सकती है। ऐसे में रूसी तेल बाजार में आने से सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कीमतों में गिरावट आएगी।

सेंसेक्स 1500 अंक गिरकर 74,500 पर आया

निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट, मेटल और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली

मुंबई, एजेंसी

अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग के बीच शेयर बाजार में आज यानी 12 मार्च को लगातार तीसरे दिन गिरावट है। सेंसेक्स 1500 अंक (1.97%) की गिरावट के साथ 74,500 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 500 अंक (2.06%) की गिरावट है, ये 23,150 पर आ गया है। आज मेटल और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट है। FMCG शेयर्स में तेजी है। अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध से सप्लाई चेन बिगड़ गई है। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 1.66% गिरकर 5,490 पर कारोबार कर रहा है। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.04% गिरकर 53,884 पर कारोबार कर रहा है। हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.48% की गिरावट के साथ 25,593

पर है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.22% नीचे 4,120 पर कारोबार कर रहा है। डाउ जोन्स 739 अंक (1.56%) गिरकर 46,677 के स्तर पर बंद हुआ। टेक बेस्ड इंडेक्स नैस्डैक कंपोजिट 1.78% गिरकर 22,311 पर बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स 103 अंक (1.52%) गिरकर 6,672 पर बंद हुआ। कच्चा तेल 100 डॉलर के पार ट्रेड कर रहा ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आज तेजी है। ब्रेंट क्रूड करीब 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। इससे पहले 9 मार्च को ब्रेंट क्रूड 120 डॉलर पर पहुंच गया था। शेयर बाजार में में यानी 12 मार्च को लगातार दूसरे गिरावट रही थी। सेंसेक्स 829 अंक (1.08%) की गिरावट के साथ 76,034 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 228 अंक की गिरावट रही।

राजनाथ सिंह-योगी ने जनता को सौंपा, तीसरे-चौथे चरण का शिलान्यास

ग्रीन कॉरिडोर फेज-2 का लोकार्पण

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर फेज-2 का आज लोकार्पण हुआ। समता मूलक चौराहा पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीता काटकर इसे जनता को सौंपा। तीसरे व चौथे फेज का शिलान्यास भी किया। रिकार्ड समय में काम पूरा होने पर श्रमिकों को सम्मानित किया। अब झूलेलाल पार्क में जन सभा को संबोधित करेंगे। गोमती नदी के दोनों किनारों पर बन रहा ग्रीन कॉरिडोर कुल 57 किलोमीटर लंबा है। इसे 4 फेज में विकसित किया जा रहा है। इस कॉरिडोर में चौड़ी सड़कें, अलग-अलग लेन, हरियाली और सुगम यातायात के लिए आधुनिक डिजाइन अपनाई गई है। अलग-अलग हिस्सों में मल्टीलेन रोड बनाई जा रही है। रक्षामंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह, सिटी मॉन्टेसरी

स्कूल के सुशांत गोल्फ सिटी कैंपस में पहुंच चुके हैं। उन्होंने यहां नए शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह के साथ मेयर सुषमा खर्कवाल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। ग्रीन कॉरिडोर योजना का दूसरा चरण 1519 करोड़ खर्च करके तैयार हुआ है। इसी के साथ योजना के तीसरे व चौथे चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी होगा, जो लखनऊ के भविष्य की रफ्तार तय करेगा। 100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर योजना के पहले चरण का लोकार्पण 11 मार्च 2024 को किया गया था। 16.8 किलोमीटर लंबा पुल आईआईएम रोड से पक्का पुल तक बना। 1220 करोड़ की लागत से इस योजना के तीसरे और चौथे चरण का शिलान्यास किया जाएगा, जो पिपराघाट से किसान पथ को जोड़ेगा। ग्रीन कॉरिडोर में 6 लेन की सड़क बनाई गई है। ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा फेज गोमतीनगर के समता मूलक चौक से निशातगंज होते हुए हनुमान सेतु डालीगंज तक है। 6 लेन सड़क बनाई गई है। दोनों ओर सड़क की चौड़ाई करीब 11.50 मीटर है। निशातगंज में चौराहा बनाया गया है। इसके शुरू होने से शहर के करीब 5 लाख लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।

6 लेन सड़क, दोनों तरफ 11.50 मीटर चौड़ा है फेज-2

ग्रीन कॉरिडोर में 6 लेन की सड़क बनाई गई है। ग्रीन कॉरिडोर का दूसरा फेज गोमतीनगर के समता मूलक चौक से निशातगंज होते हुए हनुमान सेतु डालीगंज तक है। 6 लेन सड़क बनाई गई है। दोनों ओर सड़क की चौड़ाई करीब 11.50 मीटर है। निशातगंज में चौराहा बनाया गया है। इसके शुरू होने से शहर के करीब 5 लाख लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। 1220 करोड़ की लागत से इस योजना के तीसरे और चौथे चरण का शिलान्यास किया जाएगा, जो पिपराघाट से किसान पथ को जोड़ेगा।

मेयर और डिप्टी सीएम के साथ पहुंचे सीएमएस

रक्षामंत्री और लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के सुशांत गोल्फ सिटी कैंपस में पहुंच चुके हैं। उन्होंने यहां नए शैक्षणिक भवन का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह के साथ मेयर सुषमा खर्कवाल और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। ग्रीन कॉरिडोर योजना का दूसरा चरण 1519 करोड़ खर्च करके तैयार हुआ है। इसी के साथ योजना के तीसरे व चौथे चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी होगा, जो लखनऊ के भविष्य की रफ्तार तय करेगा। 100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर योजना के पहले चरण का लोकार्पण 11 मार्च 2024 को किया गया था। 16.8 किलोमीटर लंबा पुल आईआईएम रोड से पक्का पुल तक बना।

3 घंटे से शियाओं का जोरदार प्रदर्शन

अमेरिका और इजराइल के नेताओं की तस्वीर जलाई

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में अलविदा की नमाज के बाद अमेरिका-इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने इस प्रदर्शन का ऐलान किया था। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। नमाज से पहले शहर की मस्जिदों के गेट पर जमीन पर अमेरिका-इजराइल के झंडे लगा दिए गए थे, जिन्हें नमाजी कुचलकर अंदर गए। नमाज के बाद तय ऐलान के मुताबिक लोग बड़ा इमामबाड़ा पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान बड़ा इमामबाड़ा के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर जलाई गई। इस दौरान 'नेतन्याहू आतंकवादी - ट्रंप आतंकवादी' के नारे भी लगाए गए। ऐशबाग ईदगाह स्थित जामा मस्जिद, टीले वाली मस्जिद, बड़ा

इमामबाड़ा की आसिफी मस्जिद के साथ शहर की सभी छोटी-बड़ी मस्जिदों में नमाज की गई। आसिफी में मौलाना कल्बे जव्वाद की इमामत में शिया समुदाय ने दोपहर 1 बजे नमाज किया। उसके बाद से प्रदर्शन जारी है। बड़ा इमामबाड़ा में तीन घंटे से लोग बड़ी संख्या में जमा है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ये लोग यहां पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। नकी हैदर ने कहा कि अमेरिका और इजराइल दुनिया में दो ऐसे आतंकी देश हैं जो पीड़ितों और मासूम बच्चों का खून बहा रहे हैं।

फास्ट न्यूज

बैटरी रिक्शा चालक को पीट-पीट कर मार डाला, हंगामा

कानपुर। जूही में गली के बाहर लघुशंका करने से मना करने पर दो युवकों ने बैटरी रिक्शा चालक के सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर लहुलूहान कर दिया। घटना के 9 दिन बाद बैटरी रिक्शा चालक की मौत हो गई। मृतक की बहन की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

'सौतेली मां ने 4-साल के बेटे को पीटकर मार डाला'

लखनऊ। 'मेरे 4 साल के भांजे को उसके पिता भीष्म खरबंदा और सौतेली मां रागिनी ने मिलकर मार डाला। वे उसे अक्सर करंट लगाते थे। पीटते थे। अब दोनों ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। मैं और मां (बच्चे की नानी) जब भी उससे मिलने जाते थे, उसके शरीर पर नई चोट के निशान दिखते थे। इस बार तो उसे बाथरूम में ही पीटकर मार डाला।' ये कहना है, लखनऊ में 4 साल के मासूम अर्नव (गुग्गू) की मौसी काजल का। राजधानी के चौक इलाके में गुरुवार शाम 4 साल के अर्नव की मौत हो गई। बच्चे के शरीर पर कई जगह चोट और पिटाई के निशान मिले हैं। ननिहाल वालों ने उसके पिता और सौतेली मां पर टॉर्चर कर हत्या करने का आरोप लगाया। चौक पुलिस को इसके लिए लिखित शिकायत दी है। काजल ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 4 बजे भीष्म की पत्नी रागिनी ने फोन कर सूचना दी कि अर्नव को दस्त और उल्टी हो रही थी।

यूपी एसटीएफ की छापेमारी

आजमगढ़। यूपी एसटीएफ और आजमगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान छत्तीसगढ़ से आ रही मिनी कंटेनर की तलाशी में एक करोड़ 20 लख रुपए से अधिक की कीमत का अवैध गांजा बरामद किया गया है। इस अवैध गांजे को मिनी कंटेनर ट्रक में बनी प्लास्टिक की कैविटी में छुपा कर 14 बोरियों में रखा गया था।

समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की रोज़ा इफ्तार पार्टी में शामिल हुए अखिलेश

देश में अमन-चैन और भाईचारे के लिए की गई विशेष दुआ

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी की इकाई समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल कादरी की ओर से रोज़ा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में रोज़ेदार, धर्मगुरु और शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विशेष रूप से शामिल हुए। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी भी इफ्तार कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अज़ान होते ही सभी रोज़ेदारों ने मिलकर एक साथ रोज़ा इफ्तार किया। इसके बाद नमाज़ अदा की गई, जिसमें देश में अमन-चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए विशेष दुआ की गई। इस अवसर पर आने वाले वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव की सफलता और उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की भी दुआ की गई। इफ्तार पार्टी में विधायक

रविदास मेहरोत्रा सहित शहर के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय महासचिव यामीन खान भी शामिल हुए। मौलाना सैय्यद सिराजुद्दीन अशरफ (खानकाह-ए-अशरफिया किछौछा शरीफ), मौलाना सैय्यद अदनान अशरफ, मौलाना सैय्यद समदानी अशरफ, मौलाना सैय्यद समनानी अशरफ, मौलाना सैय्यद यजदानी अशरफ, हजरत मुफ़्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली, मौलाना अफ्फान अतीक फिरंगी महली, मौलाना यासूब अब्बास, मौलाना अब्दुल्ला नदवी और मौलाना फरमान नदवी (इमाम नदवा) सहित अनेक धर्मगुरु और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

दोनों पैर में गोली मारी, जॉइन करने आए नए डीजीएम डरकर मुंबई लौटे

हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 2 अफसरों के हत्यारोपी का एनकाउंटर

तमसा संकेत, एजेंसी

बदायूं। बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के DGM सुधीर गुप्ता (55) और असिस्टेंट मैनेजर हर्षित मिश्रा (35) की हत्या के आरोपी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में पुलिस ने गोली मारी। इसके बाद कंधे पर लादकर गाड़ी तक ले गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CO डॉ. देवेंद्र सिंह ने बताया- आरोपी ठेकेदार अजय प्रताप सिंह ने जिस हथियार से अफसरों की हत्या की थी, उसे वारदात के बाद जंगल में छिपा दिया था। शुक्रवार तड़के पुलिस हथियार की बरामदगी के लिए आरोपी को जंगल में ले गई थी। इसी दौरान आरोपी ने झाड़ियों के बीच से

लोडेड तमंचा निकाला और पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में वह जख्मी हो गया। इस पूरे हत्याकांड में बदायूं पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोपी अजय प्रताप सिंह आउटसोर्स कर्मचारी था और प्लांट में पराली की सप्लाई का ठेका लेता था। लेकिन, इसे नौकरी से निकालकर इसकी फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। इसके बाद अजय करीब तीन महीने से DGM सुधीर गुप्ता को जान से मारने की धमकी दे रहा था। सुधीर गुप्ता ने 4 फरवरी को मुसाझाग थाने में अजय के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि अजय लगातार धमका रहा है। उनका पीछा करता है। सुधीर गुप्ता इतना डर गए थे कि उन्होंने रिटायरमेंट के 5 साल पहले ही VRS की एप्लिकेशन दे दी थी, जो मंजूर हो गई थी। 31 मार्च को उनकी नौकरी का आखिरी दिन था। वहीं, हर्षित मिश्रा ने भी अपने ट्रांसफर के लिए एप्लिकेशन दी थी। लेकिन, उससे पहले ही आरोपी ने दोनों की हत्या कर दी। FIR के बाद भी बदायूं पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। गुरुवार को सुधीर की जगह नए डीजीएम लोकेश भी मुंबई से जॉइन करने के लिए HP प्लांट पहुंचे थे। उनके सामने ही वारदात हुई। इसके बाद वह इतना डर गए कि पुलिस उन्हें बरेली एयरपोर्ट तक छोड़कर आई। वह मुंबई स्थित अपने घर लौट गए। अब डबल मर्डर के बाद पुलिस ने लीपापोती करते हुए थाना प्रभारी अजय कुमार और हल्का प्रभारी SI धर्मेन्द्र कुमार को सस्पेंड कर दिया।

डीजीएम के सीने में धंसी मिली दो गोलियां, मैनेजर के दिल के आर-पार हुई बुलेट

गुरुवार देर रात दोनों अफसरों के शव का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक, डीजीएम के सीने में दो गोलियां धंसी मिलीं, जबकि असिस्टेंट मैनेजर हर्षित के सीने के बाईं ओर एक गोली लगी, जो दिल को चीरते हुए पार निकल गई।

पूर्व सांसद शिवदयाल सिंह चौरसिया की जयंती पर समाजवादी पार्टी ने दी श्रद्धांजलि

लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय और प्रदेश के जिला कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित

तमसा संकेत, संवाददाता

पूर्व सांसद और लखनऊ के प्रसिद्ध समाजसेवी शिवदयाल सिंह चौरसिया की जयंती शुक्रवार को समाजवादी पार्टी को के राज्य मुख्यालय सहित प्रदेश के विभिन्न जिला कार्यालयों में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और उनके सामाजिक व राजनीतिक योगदान को स्मरण किया। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में शिवदयाल सिंह चौरसिया के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष Shyam Lal Pal ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नमन किया और उनके समाजसेवा के कार्यों को याद किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद अरविंद कुमार सिंह, दंडी स्वामी बद्रीनाथ, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष शुभम गिरि, पूर्व मंत्री

रामलखन चौरसिया, पूर्व विधायक सुभाष राय, असम प्रदेश अध्यक्ष ब्रोजेन कुमार हैंदिक, पार्षद रामनरेश चौरसिया, व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, डॉ. अजय चौरसिया, प्रोफेसर भुवन जोशी, एस.के. राय, मोहम्मद याकूब खान, अरशद खान, किसान शकील त्यागी, मोहम्मद अजमल, जुलेत तालुकेदार, पवन यादव, के.के. यादव और प्रियंका चौरसिया सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके अलावा मनोज चौरसिया, अक्षय जैन अरिहंत, चौधरी भोपाल सिंह, चौधरी सोमेश्वर प्रताप, पियूष जोशी, श्रीमती जमुना चौधरी, जसपाल चौहान, अमन राजपूत, संजय यादव, अभिषेक गुप्ता, अंकित चौरसिया, दीपक यादव, हरीश चौरसिया, सुरेश चौरसिया, संदीप सिंह, रामबाबू चौरसिया, पंकज चौरसिया, कमलेश चौरसिया, अनुराग चौरसिया, अभिषेक चौरसिया और पवन चौरसिया समेत बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी।

हादसा : ड्यूटी से घर लौटने के बाद निकले थे बाहर, गेटमैन की सूचना पर पहुंची पुलिस

लेखपाल ने ट्रेन के आगे लेटकर दी जान

तमसा संकेत, एजेंसी

शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में लेखपाल ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। वह ड्यूटी खत्म कर घर लौटे थे। इसके बाद किसी काम से घर से बाहर निकले थे। इसी दौरान वह रेलवे फाटक के पास पहुंच गए। ट्रैक के पास खड़े होकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। जैसे ही ट्रेन नजदीक आई, लेखपाल तुरंत पटरी पर लेट गए। ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। उनका धड़ उछलकर करीब 25 मीटर दूर जा गिरा। ट्रेन गुजरने के बाद गेटमैन उनके पास पहुंचा। पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। सुसाइड का कारण अभी सामने नहीं आया है। पुलिस घरवालों से पूछताछ कर रही है। मामला सदर बाजार क्षेत्र का है। अमरदीप सक्सेना चौक कोतवाली क्षेत्र के बिजलीपुरा में रहते थे। वह तिलहर तहसील के गढ़िया रंगीन में तैनात थे। अमरदीप गुरुवार देर शाम ड्यूटी से घर लौटे। कुछ देर रुकने के बाद वे फिर से

सरकारी काम के लिए पैदल घर से निकल गए। इसके बाद वह सीधे सदर बाजार क्षेत्र के इंदरानगर रेलवे फाटक पहुंचे। उस समय फाटक बंद था। फाटक क्रॉस कर पटरी के पास खड़े हो गए और ट्रेन का इंतजार करने लगे। ट्रेन को देखते ही उन्होंने दो बार पटरी पर लेटने की कोशिश की। इसके बाद जैसे ही ट्रेन नजदीक आई तो तुरंत पटरी पर पीठ के बल लेट गए। ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। इसके चलते धड़ दूर जाकर गिरा। इस पूरे हादसे को वहां खड़े गेटमैन ने देखा। लेकिन, जब तक वह कुछ समझ पाते, तब तक हादसा हो चुका था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव की पहचान के बाद पुलिस ने परिवारवालों को हादसे की सूचना दी। रोते-बिलखते घरवाले पोस्टमॉर्टम हाउस पहुंचे। हादसे की सूचना पर एसडीएम सदर और तहसीलदार भी वहां पहुंचे।

- ट्रेन के पास आते ही तुरंत लेखपाल पटरी पर लेट गए। गेटमैन और पास खड़े लोग कुछ समझ ही नहीं पाए।
- लेखपाल अमरदीप सक्सेना तिलहर तहसील की गढ़िया रंगीन में तैनात थे।

लेखपाल का जल्द प्रमोशन होने वाला था

एम्स से चल रहा था इलाज, SIR में ड्यूटी लगी थी

एसडीएम तिलहर सदानंद सरोज के अनुसार, लेखपाल के भाई ने बताया कि लेखपाल का काफी समय से दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। वह दवा खाने से काफी तनाव में थे। लेखपाल की वर्तमान में कटरा विधानसभा में SIR में ड्यूटी चल रही थी।

घरवालों ने बताया कि लेखपाल कुछ समय से डिप्रेशन में थे। करीब 3 महीने पहले उनके प्रमोशन की फाइल भी शासन को भेजी गई थी। कुछ समय बाद वह कानूनगो हो जाते। कुछ दिन पहले उन्होंने बेटी की सगाई की थी।

पृष्ठ 01 का शेष...

भारत हमारा दोस्त...

बताया जा रहा है कि उनकी हालत बेहद गंभीर है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में चोट इतनी गहरी थी कि उनका एक पैर काटना पड़ा और लिवर को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। अस्पताल के एक हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया गया है और वहां भारी सुरक्षा तैनात है। मुजतबा खामेनेई को उनके पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद 9 मार्च को देश का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया था। अली खामेनेई की 28 फरवरी को मौत हुई थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रणनीति की आलोचना की है। बोल्टन का कहना है कि ट्रम्प ने ईरान को लेकर हालात का गलत आकलन किया> उन्होंने कहा- ट्रम्प को शायद लगा था कि अमेरिका ईरान में भी वैसा ही सत्ता परिवर्तन करा सकता है जैसा उसने वेनेजुएला में करने की कोशिश की थी। लेकिन ईरान, वेनेजुएला नहीं है। बोल्टन ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रम्प अक्सर बड़े फैसले बिना प्लानिंग के ले लेते हैं। उनके अनुसार राष्ट्रपति कई बार "तुरंत फैसले" करते हैं और दीर्घकालिक रणनीति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। हालांकि बोल्टन ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना का प्रदर्शन अब तक मजबूत रहा है और ईरान की कुछ सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान को जल्दी झुकाने की उम्मीद करना गलत साबित हो सकता है। हालांकि बोल्टन ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना का प्रदर्शन अब तक मजबूत रहा है और ईरान की कुछ सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाया गया है।

एलपीजी संकट...

ऐसे समय में विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए, लेकिन वह गैर-जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने संसद परिसर में LPG संकट के खिलाफ प्रदर्शन किया। इधर, PTI के सूत्रों ने बताया कि TMC ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के खिलाफ दोनों सदनों में प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 लाख करोड़ का आर्थिक स्थिरीकरण कोष (Economic Stabilization Fund) भारत को वित्तीय गुंजाइश देगा, जिससे वह वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके। उन्होंने कहा कि यह कोष एक 'बफर' (सुरक्षा कवच) के रूप में काम करेगा, जो पश्चिम एशिया जैसी मौजूदा अप्रत्याशित वैश्विक चुनौतियों से पैदा होने वाले झटकों को झेलने में मदद करेगा। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय हित में एक साथ आना चाहिए। इस तरह से बात करनी चाहिए, जिससे जनता को भरोसा मिले और उनमें उम्मीद जगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि, विपक्ष का मानना है कि सदन के वेल में घुसकर नारे लगाना ही उनकी एकमात्र भूमिका है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और एक खेदजनक स्थिति को दर्शाता है। मुझे नहीं पता कि और क्या कहूं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- विदेशों में हो रहे घटनाक्रमों के कारण हमारे देश के सामने कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन चुनौतियों का सामना करने, जरूरी फंड मुहैया कराने और पूरी तरह तैयार रहने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे समय में विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए और आम लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए। इसके बजाय वे ऐसे गैर-जिम्मेदाराना कदम उठाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- यह विडंबना है कि जब मैं बता रही हूं कि सरकार सप्लाई चेन में रुकावटों और LPG से जुड़ी समस्याओं समेत किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना करने के लिए कैसे तैयारी कर रही है, तब भी वे (विपक्ष) मेरा जवाब सुनने को तैयार नहीं हैं। वे अपना ही एजेंडा चलाना चाहते हैं। यही है हमारा विपक्ष।

पेट्रोल-डीजल की...

यह लोगों के बीच घबराहट के कारण हो रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा- LPG चिंता का विषय है क्योंकि देश का ज्यादातर LPG स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है और वह अभी बंद है। हालांकि, हमारे 25,000 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स में से किसी पर भी गैस खत्म होने (ड्राई आउट) की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मंत्रालय ने आगे कहा- केंद्र की तरफ से राज्यों को अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसिन आवंटन किया गया है। राज्यों से अपील की गई है कि वे जिलों में केरोसिन बांटने लिए जगह तय करें। वैकल्पिक ईंधन विकल्पों के लिए कोल इंडिया को छोटे, मध्यम और अन्य उपभोक्ताओं को कोयला उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि LPG की पैनिक बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी LPG डीलर पर गैस खत्म होने की स्थिति सामने नहीं आई है। 9 मार्च 2026 को जारी नेचुरल गैस ऑर्डर के तहत कई सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। उसी आदेश के अनुसार घरेलू पीएनजी (PNG) और सीएनजी (CNG) की आपूर्ति बिना किसी कटौती के जारी है।

गोमतीनगर की शिवराम दुलार गौशाला पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद

गौशालाओं में गायों के संरक्षण और उचित उपचार व्यवस्था पर दिया जोर

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। गोमतीनगर लखनऊ के ग्राम जगपाल खेड़ा मजरा भरवारा स्थित शिवराम दुलार गौशाला में परमपूज्यनीय ज्योतिर्मठ बद्रीकाश्रम पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पधार कर वहां मौजूद गायों की पूजा की। उन्हें माला पहनाई फिर मिष्ठान्न और फल खिलाए। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गौमता का भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हें पूजा जाता है। हमें गौशालाओं में गौमाता का उचित संरक्षण करना चाहिए। उनकी सेवा सुश्रुषा के साथ चिकित्सा उपचार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस मौके पर गौशाला के संचालक श्री अनुराग मिश्र ने शंकराचार्य जी का स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम में सर्वश्री डॉ. रमेश दीक्षित, राजेन्द्र यादव पूर्व विधायक, सुश्री पूजा शुक्ला, श्रीमती ममता रावत सभासद, पंडित अरूण मिश्रा, धर्मेन्द्र सिंह, अभिषेक दीक्षित, अतहर हुसैन सहित स्थानीय डीफ स्कूल के मूक, बधिर बच्चों की भी इस मौके पर विशेष मौजूदगी रही।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676